(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश में कार्यरत डाक व तार विभाग के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां, ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । जैसाकि अनुलग्नक में है ।

विवरण

उज्जैन रेलवे डाक सेवा के कुछ कर्मचारियों ने उज्जैन विकास प्राधिकरण से सीधे खरीद आधार पर बने बनाए मकान खरीदने के लिए गृह निर्माण अग्रिम मंजूर करने के लिए आवेदन किया था । इन कर्मचारियों ने स्वयं संसाधनों से लागत का एक अंश जमा करने के बाद मकानों का कब्जा ले लिया है । तब विकास प्राधिकरण ने उन्हें मकान की शेष कीमत जमा करने का निर्देश दिया था । चूंकि इसके पूर्व कि गृह निर्माण अग्रिम को मंजूरी दी जा सके उन्होंने मकानों का कब्जा ले लिया था, इसलिए उनके मामलों को पी. एम. जी. भोपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था । इन कर्मचारियों ने उनके मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन दिया है ।

Feasibility Report of Sethusamudram Project

*87. SHRI V. GOPALSAMY:

SHRI V. VENKA:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Committee appointed by Government to make further study on the feasibility of Sethusamudram Project and to examine the economic viability of the Project has since submitted its report; and

(b) if so, what are the findings and recommendations thereof?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

मस्कत जेल में भारतीय राष्ट्रिक

*88. श्री रामनरेश कुशवाहा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मस्कत जेल में तीस भारतीय राष्ट्रिक बन्द हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें छुड़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस समय 40 भारतीय ओमान में नजरबन्द है जिनमे से 34 भारतीय मस्कत की जेल में हैं और 6 सलाला में ।

(ख) 25 भारतीय राष्ट्रिक ओमान में अवैध रूप से आप्रवासन के आरोप में पकड़े गए हैं। इनमें से 15 को शीघ्र रिहा और भारत प्रत्यावर्तित/उद्वासित किया जा रहा है और शेष व्यक्तियों का भी उनके बारे में पक्की जानकारी हासिल होते ही भारत भेज दिया जाएगा।

अन्य कैदी विभिन्न आपराधिक कार्यवाहियों के लिए जेल में हैं और उनको उक्त सजा की अवधि पूरी होने पर ही रिहा किया जाएगा।

इन भारतीय राष्ट्रिकों को सभी कौंसली सहायता दी गई है और दी जा रही है।

Allotment of land to National Co-operative Union by D.D.A.

*89. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the National Cooperative Union was allotted a piece of land in the Hauz Khas area of New Delhi by the D.D.A.; and

(b) when the allotment was made, what was the area of the land originally allotted, conditions of allotment, and the area now under the occupation of the said organisation?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) and (b) A plot measuring 3.04 acres was initially allotted to the Union in September, 1968. In 1976 it was found, on re-demarcation, that the actual area of the plot was 3.128 acres and the excess was allowed to remain with the Union. The allotment was governed by the standard terms and conditions of the lease deed which was executed by the Union on 18-11-77.

Danish Government aid for ruarl water supply schemes

*90. SHRI GHOUSE MOHIUDDIN SHEIKH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Government of Denmark have offered to provide grant to implement rural water supply schemes in the country;

(b) if so, the amount expected from the Government of Denmark for this purpose; and

(c) the States which have been selected to provide drinking water under this scheme?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (c) Two Rural Water supply Projects in the States of Tamil Nadu and Karnataka assisted by the Government of Denmark are already under implementation. The assistance to be received for these two projects is in the shape of rigs and other equipment at an estimated cost of 16.0 million Danish Kroner (Rs. 2 Crores) and 19.7 million Danish Kroner (Rs. 2.5 Crores) respectively.

2. The Government of Denmark have also agreed to assist another project for rejuvenation of hand pumps in the districts of Salem and South Arcot in Tamil Nadu State. The equipment assistance expected is of the order of Rs. 72 lakhs.

3. A proposal for a Rural Water Supply Project in the Saline Belt of Orissa is under consideration. A Side Letter for extending financial assistance of Rs. 1.24 Crores for the preparatory phase of the project is expected to be signed between the two countries.